

MMs Refine Milan Nagar House Design

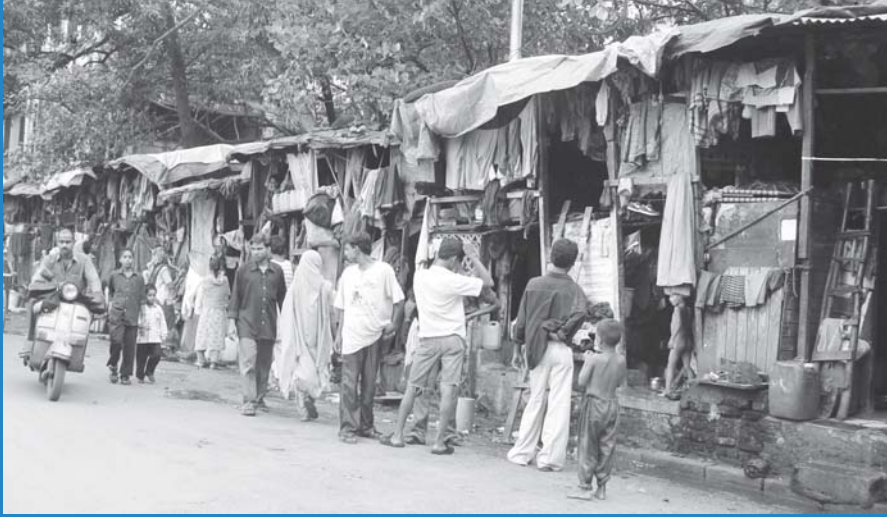
AS OF April 2005, the first of four buildings of the Milan Nagar Housing project – Mumbai's first project to resettle pavement dwellers – is almost complete. It has taken longer than expected to build because of its complicated design which divides each tenement into three levels, creating pri-

vate spaces for different generations living together.

Since the costs of this design are fairly high, and many households don't want 'levels', the Byculla Mahila Milan is in the midst of considering other options and making a mid-course correction. Mahila Milan leader Bano explained

that the next building would have just two split levels, similar to the original design that the group had created some 18 years ago.

Shakoorbhai of Byculla added, "This present type of construction takes double, sometimes triple, the amount of time. So we are considering other designs because our priority is now to move in quickly and create a model that saves on money and time."



FROM PAVEMENT TO PUCCA HOMES: An eighteen year old dream came true when Mumbai's first housing project for pavement dwellers began coming up at Milan Nagar. The permission to get land and start building took eighteen hard years of work but finally the construction got underway. One Mahila Milan leader is always on site to supervise the work. Other leaders visit on a weekly basis to oversee work done and payments to be made.

फुटपाथ से पक्के घरों तक: अठारह साल पुराना सपना साकार हुआ जब मिलन नगर में मुंबई के फुटपाथवासियों की पहली आवास परियोजना निर्माणाधीन है। जमीन मिलने में और निर्माण की स्वीकृति मिलने में 18 कठिन साल लगे पर आखिरकर निर्माण चालू है। महिला मिलन की एक नेता काम की देख रेख करने हमेशा साइट पर रहती है। अन्य नेता सप्ताह में एक बार देखने आते हैं कि कितना काम हुआ है और क्या भुगतान करने हैं।

महिला मिलन ने मिलन नगर के डिज़ाइन को सुधारा



अप्रैल 2005 तक, मिलन नगर आवास योजना की चार में से पहली इमारत लगभग तैयार है – यह मुंबई की पहली परियोजना है जहां फुटपाथवालों

के पुनर्वसन के लिये चार तीन-मंज़िली इमारतें बनाई जाएंगी। इसके निर्माण में आशा से अधिक समय लगा क्योंकि इसका डिज़ाइन बहुत जटिल था। इसमें हर घर को तीन स्तरों में बांटा गया था जिससे कि साथ रह रही हर पीढ़ी को निजी जगह मिल सके।

इस डिज़ाइन का खर्च काफी ज्यादा है, इसलिये भायकला महिला मिलन बाकी की तीन इमारतों के लिये विकल्प सोच रही है। महिला मिलन नेता

बानू ने बताया कि अगली बिल्डिंग में सिर्फ दो स्तर होंगे, उसी डिज़ाइन से मिलते जुलते जो उनके ग्रुप ने कुछ 18 साल पहले बनाया था।

भायकला के शकूर भाई ने कहा, "इस अभी वाले निर्माण में दुगना और कभी कभी तिगुना समय भी लग जाता है। इसलिये अब हम दूसरे डिज़ाइन भी देख रहे हैं क्योंकि अब हमें जल्द से जल्द वहां जाना है; ऐसा मॉडल बनाना चाहिये जो पैसे और समय की बचत करे।



MM LEADERS BRIEF SACHS:

World-famous Columbia University economist Jeffery Sachs (*in pic with SPARC's Sheela Patel*) currently on the Millennium Development Goals Task Force, met Mahila Milan leaders at the Byculla Area Resource Centre mid-2004. They told him of how the Federation had taught them to think collectively and solve problems pro-actively.

महिला मिलन नेताओं ने सैक्स को दिया विवरण

विश्व प्रसिद्ध हार्वर्ड अर्थशास्त्री जैफरी सैक्स, जो आजकल मिलेनियम विकास लक्ष्यों के टास्क फोर्स में हैं, 2004 मध्य में भायकला एरिया रिसोर्स सेंटर आए जहां वे वडाला, कोकरी आगार और भायकला की महिला मिलन नेताओं से मिले। उन्होंने बताया कि संगठन ने उन्हें सामूहिक रूप से सोचना और सक्रिय तरीके से समस्याओं का समाधान करना सिखाया है। उसने उनकी क्षमताएँ विकसित कीं जिससे कि वे संगठन में काम कर सकें और एक बड़े और शक्तिशाली ग्रुप का भाग बन सकें।

These Slum Development Plans Have No Place for Slum Dwellers!

DEVELOPER Mukesh Mehta is in the news because of his plans to redevelop Dharavi, “the largest slum in Asia”. The plan which envisages global competitive bidding for the development of different sectors in Dharavi apparently has the backing of the Maharashtra Government.

Dharavi, spread over some 430 acres of land was invented by India's poor who came from its different states to Mumbai, reclaimed the marshy land and made it habitable. Today, Dharavi's six lakh people form a vibrant, cosmopolitan community. A people of diverse ethnic, linguistic and religious backgrounds.

A home both to the poor and the better-off. Here you will find an astonishingly wide range of economic activity – from those who make *idlis* to potters to tanners to manufacturers of airline cutlery and crockery. There are workers who make only Rs. 300 a month and there are a few entrepreneurs who earn even Rs. 300,000 a month. There are potters making Diwali diyas with smuggled clay which you and I buy at very cheap rates. Scrap and garbage recycling are major sources of income generation here. Alongside, we also know that at least 21 children of Dharavi are studying in medical college and more than 40 are doing engineering courses.

What will happen to all these people if Mukesh Mehta's plans are implemented? More likely than not they will be pushed out of Dharavi as it transforms itself into multi-storeyed apartments and glitzy commercial establishments. The Government has agreed to give an FSI of 4, paving the way for skyscrapers. We doubt that the present residents of Dharavi will be able to afford to live in gleaming high-rises. Dharavi, so close to the Bandra-Kurla complex, the planned international financial centre of the city with its diamond bourses and its multi-national offices, will cater to the needs of the better-off and the wealthy.

The experience of more than 50 years of development in the Third World has conclusively proved that the top-down approach of paternalistic, sometimes socialist, States has not worked. Elites decide what is good for the people and predictably, these decisions do not work in favour of the poor. Has Mehta engaged in any consultation with the residents of

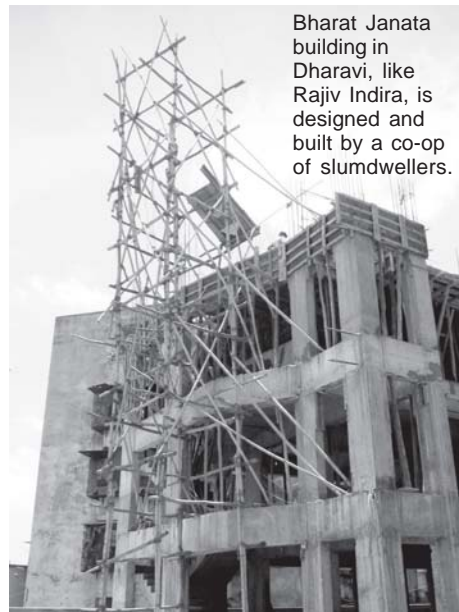
Dharavi, much less the poor among them? There are more than 400 housing co-operatives of slum dwellers here but has Mehta discussed his plans with even one? When we try to make Mumbai like Shanghai, let's remember China is not famous for democratic decision-making.

There is another way in which Dharavi can be redeveloped – by adopting a bottom-up approach, through community participation, by drawing up plans that are people-centered, and by addressing the livelihood concerns of the poor. Mr. Mehta, we are not against global capital or skyscrapers or the pursuit of profit per se – but does all this have to be at the cost of the poor? That's the important question to answer.

(Extract from article in 'Good Governance' by A. Jockin, Sheela Patel and Sundar Burra)



Housing



Bharat Janata building in Dharavi, like Rajiv Indira, is designed and built by a co-op of slumdwellers.

धारावी स्थित भारत जनता इमारत। राजीव इंदिरा की तरह झोंपड़पट्टीवासियों ने इसका डिजाइन बनाया है और निर्माण किया है।

वित्त केन्द्र बनाने की योजना है और जहाँ हीरों का बाजार और बहुराष्ट्रीय ऑफिस हैं। इसलिये धारावी मध्यम और अमीर वर्गों की जरूरतों को ज्यादा पूरा करेगा।

तीसरी दुनिया में काम करने के 50 वर्षों से अधिक के अनुभव ने सिद्ध कर दिया है की राज्यों का ऊपर से नीचे का पितृवत, कभी कभी समाजवादी तरीका कारगर नहीं होता। अभिजात वर्ग निर्णय करता है की लोगों के लिये क्या अच्छा है; और साफ है कि ये निर्णय गरीब के पक्ष में काम नहीं करते। क्या मेहता ने धारावी के रहने वालों से कोई बातचीत की है? गरीब की तो बात ही छोड़ दो। यहाँ झोंपड़पट्टीवासियों की 400 से अधिक आवासीय संस्थाएँ हैं, लेकिन क्या मेहता ने एक से भी बातचीत की है? जब हम मुंबई को शांघाई बनाने की कोशिश करते हैं तो यह याद रहे की चीन लाकतांत्रिक निर्णय लेने के लिये प्रसिद्ध नहीं है।

धारावी के पुनर्विकास का एक और भी तरीका है – नीचे से ऊपर का रास्ता। समुदायिक भागीदारी द्वारा ऐसी योजनाएँ बनायें जो जन केंद्रित हों और जो गरीबों के रोजगार की जरूरतें ध्यान में रखें। श्री.मेहता हम अंतर्राष्ट्रीय वित्त या गगनचुंबी इमारतों या फायदे के सौदों के खिलाफ नहीं हैं – पर क्या यह सब गरीब की कीमत पर होना चाहिये? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।

(‘गुड गर्वनेस’ में ए.जोकिन, शीला पटेल एवं सुंदर बुरा के लेख से उद्धरित)

झोंपड़पट्टीवासियों के बिना झोंपड़पट्टी विकास योजना!

विकासक मुकेश मेहता समाचारों में हैं ‘एशिया की सबसे बड़ी झोंपड़पट्टी’ धारावी, के पुनर्विकास की अपनी योजनाओं के कारण। ऐसी योजना जिसमें धारावी के विभिन्न टुकड़ों के विकास के लिये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बोली लगाने का विचार है और जिसे शायद महाराष्ट्र सरकार का समर्थन भी है।

धारावी 430 एकड़ जमीन पर फैला है और अलग अलग राज्यों से मुंबई आये भारत के गरीबों द्वारा बनाया गया है जिन्होंने दलदली जमीन को रहने लायक बनाया। आज धारावी में भिन्न भिन्न जाति, भाषा और धर्मों के छः लाख लोगों का जीवंत, सर्वप्रांतीय समुदाय है।

यहाँ गरीब और अमीर दोनों के घर हैं। यहाँ आश्चर्यचकित करने वाली आर्थिक गतिविधियाँ चलती हैं – इडली बनाने वालों से लेकर कुम्हारों से लेकर चमड़ा कारीगरों से लेकर वायुयानों के लिये चीनी मिट्टी के बर्तन और चम्मच आदि के उत्पादकों तक। यहाँ ऐसे मजदूर हैं जो सिर्फ रु. 300 प्रति माह कमाते हैं और यहाँ ऐसे उद्यमी भी हैं जो रु.300,000 प्रति माह कमाते हैं। यहाँ कुम्हार तस्करी की मिट्टी से दीवाली के दिये बनाते हैं जो आप और हम काफी सस्ते दामों में खरीदते हैं। रद्दी और कचरे का काम यहाँ आय का एक मुख्य साधन है। साथ ही हम धारावी के कम से कम 21 ऐसे बच्चों को जानते हैं जो मेडिकल कॉलेजों में पढ़ रहे हैं और 40 ऐसे हैं जो इंजीनियरी कर रहे हैं।

यदि मुकेश मेहता की योजना कार्यान्वित हो गयी तो इन सब का क्या होगा? जैसे जैसे यहाँ बहुमंजिली इमारतें और जगमगाते व्यवसायिक प्रतिष्ठान बनते जायेंगे, कभी न कभी इन्हें धारावी के बाहर धकेल दिया जायेगा। सरकार ने 4 की एफ.एस.आई. देने की मंजूरी दे दी है और गगनचुंबी इमारतों के लिये रास्ता खोल दिया है। हमें शक है कि धारावी के वर्तमान रिहायशी इन चमचमाती इमारतों में रह पायेंगे। धारावी उस बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स के पड़ोस में है जिसे शहर का अंतर्राष्ट्रीय



THE success of the Alliance's first housing project for *bidi* workers in Sholapur, initiated in 1998, has resulted in more offers speeding the Alliance way.

Sholapur is a city with hundreds of thousands of *bidi* (Indian cigarettes) workers, mostly women, working in co-operatives that roll *bidis* for various brands. Although a Central-State Govt. housing subsidy does exist for *bidi* workers, they have unfortunately not been able to access it. As a result, almost all live in rented homes in various parts of the city – while dreaming of a home and workplace of their own.

One of the reasons the *bidi* workers do not access the subsidy is that the government prototype for housing is too expensive. The subsidy barely covers half the construction costs and the workers cannot afford to put in the remaining amount.

In 1998, the Alliance held a housing exhibition demonstrating a substantially cheaper model where two-thirds of the cost was met by the subsidy. It then gave a loan to members of the Maa Saheb Bidi Kamgar Griha Nirman Sanstha for the remaining amount. As the construction got underway, members regularly saved towards repayment, the monies being deposited in the Sanstha or Society account.

There was yet another catch – you can't access the housing subsidy if you don't have land! In effect, the ability to get a loan to purchase land leverages a subsidy. Sholapur-Phase I therefore used a loan from the Alliance to purchase land.

As part of Phase I, 500 houses were built. All of them were registered in the women's names.

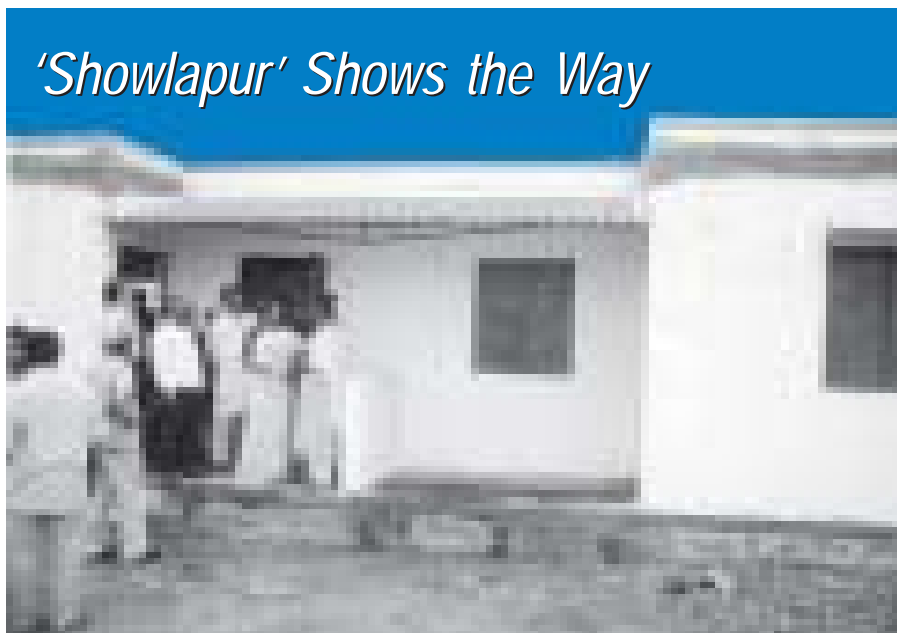
Attracted by the success of the first project, the Alliance was approached by more than 2,000 other members of the same Union. >

शोलापुर ने दिखाया रास्ता

गठबंधन द्वारा 1998 में शोलापुर के बीड़ी कामगारों के लिये शुरू की गयी पहली आवास योजना की सफलता के परिणामस्वरूप और भी कई प्रस्ताव आये हैं। शोलापुर शहर में कई हजार बीड़ी मजदूर, मुख्यतः महिलाएँ, अलग अलग सहकारी बीड़ी उद्योगों में काम करती हैं। हालांकि बीड़ी मजदूरों के लिये एक केन्द्र-राज्य सरकार का आवास परिदान है, दुर्भाग्य से वे इसे ले नहीं पाये हैं। इसका नतीजा है कि लगभग सभी मजदूर शहर के अलग अलग इलाकों में किराये के घरों में रहते हैं – और अपने खुद के घर और काम की जगह के सपने देखते हैं।

परिदान न लेने का एक कारण है कि घर का सरकारी नमूना बहुत महंगा है। परिदान राशि से मुश्किल से निर्माण का आधा खर्चा निकलता है और मजदूरों में बाकी पैसे लगाने की हैसियत नहीं है। गठबंधन ने 1998 में एक आवास प्रदर्शनी रखी थी जिसमें उसने काफी सस्ता मॉडल दिखाया जिसका दो-तिहाई खर्चा परिदान से निकल रहा था। और बाकी राशि के लिये उसने संस्था के सदस्यों को ऋण दिया। जैसे जैसे निर्माण शुरू हुआ सदस्यों ने नियमित भुगतान चालू कर दिये।

एक रुकावट और थी – यदि आपके पास जमीन न हो तो आप आवास परिदान नहीं उठा सकते। यानी की, यदि आप जमीन खरीदने के लिये ऋण लेने की क्षमता रखते हो तो परिदान मिलेगा।



The Sholapur model-Phase 1 not only inspired 2,000 more members of the same Union to build similar homes, it has roused the interest of the Municipality as also the State Govt. in taking up similar projects.

शोलापुर मॉडल-चरण 1 ने न केवल उसी यूनियन के अन्य 2000 सदस्यों को घर बनाने के लिये प्रेरित किया, इसके कारण नगरपालिका और राज्य सरकार भी ऐसी परियोजनायें शुरू करने में रुचि दिखा रहे हैं।

बीड़ी मजदूरों ने अपने साधन इकट्ठे किए और लगभग रु.1.4 करोड़ का ऋण लिया (जिस पर वह जबरदस्त 18 प्रतिशत ब्याज दे रहे थे) लगभग 70 एकड़ जमीन खरीदने के लिए। एक दूसरी आई.आई.डी. ग्रांट की मदद से गठबंधन ने इस ऋण का भुगतान किया और जमीन मां साहिब निर्माण संस्था के नाम से ट्रांसफर की। इसके बाद इसके सदस्यों ने स्पार्क के निर्माण खंड, एस.एस.एन.एस.के साथ विकास समझौता किया कि वे 2500 घर और कुछ समुदायिक कामों के लिये शेड बनाएं।

इस दूसरे चरण का डिज़ाइन कुछ ऐसा है कि क्लिफ – एक संसाधन वित्त सुविधा – निर्माण की लागत के लिए ब्रिज फंड देगा और एक बार सब्सिडी मिलने के बाद मजदूर पैसे वापस दे देंगे। सारी प्रक्रिया का लेखन भी चल रहा है जिससे कि इसे अन्य लोगों में फैलाया जा सके।

शोलापुर परियोजनाओं की सफलता ने नगरपालिका का ध्यान आकर्षित किया है और अब वे भी भाग लेना चाहते हैं। शोलापुर के आस पास के जिले भी इन परियोजनाओं से सीखना चाहते हैं और श्रमिक कल्याण मंत्रालय इस परियोजना के अनुभव को अन्य राज्यों के साथ बांटना चाहता है।

शोलापुर-प्रथम चरण में गठबंधन के फंडर आई.आई.डी. ने जमीन खरीदने के लिये ग्रांट दी। कुल 500 घर बने और सभी महिलाओं के नाम से रेजिस्टर किये गये। इस पहली योजना की सफलता से आकर्षित हो कर गठबंधन के पास पहले से ही रेजिस्टर हुई एक गृहनिर्माण संस्था मां साहेब बीड़ी कामगार गृह निर्माण संस्था आयी। 2000 से अधिक बीड़ी कामगार या मजदूर इसके सदस्य थे। उनकी अर्जी और कागजात स्पार्क, महिला मिलन, एन.एस.डी. एफ. की एक कमेटी ने वकीलों के साथ मिल कर देखे।

पिछले साल जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों वाले कुछ

>Their application and documentation was reviewed by a committee of SPARC, Mahila Milan and NSDF as also legal consultants.

This second group of bidi workers who owned small plots pooled resources and borrowed a large sum of money last year (on which they were paying a hefty interest) to purchase an extensive plot of about 70 acres. The Alliance got the plot transferred in the name of the Maa Saheb Union. Its members then entered into a development agreement with SPARC's sister-organisation SSNS, to start planning for 2500 more houses and some collectively-owned workshops.

This second such a way that (structure financing facility) construction, and will subsidy comes in. The being documented so disseminated.



Housing

phase is designed in CLIFF* (an infrastructure will bridge the cost of be repaid once the sub-whole process is also that it can be widely

The success of the Sholapur projects has roused the interest of the Municipality which would like to be involved. Groups in districts around Sholapur are also keen to learn from these projects, while the Labour Welfare Ministry plans to share this project experience with other States.

Two lessons emerge very clearly. First, that it is critical for the poor to have access to bridge finance because very often subsidies only come through after the project is complete. And second, it is only with the help of organised communities like the NSDF that isolated groups can access subsidies.

***WHAT IS CLIFF?** CLIFF (or Community Led Infrastructure Finance Facility) is a financing mechanism that provides organizations of the urban poor direct access to the venture capital they need to show their capacity to develop creative and sustainable solutions to problems in slums. These approaches are almost by definition, experimental. They test out ideas on a small scale, then seek to scale them up, so that large numbers of people can benefit. The finance helps cities plan on basis of long-term pragmatic solutions rather than short-term or isolated pilot projects.



क्लिफ के बारे में

क्लिफ या कम्युनिटी लेड इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग फैसिलिटी एक नवीन प्रयास है। जहां अंतरराष्ट्रीय दाता संस्थाएँ मूलधन और ग्रांट उपलब्ध कराती हैं। इससे शहरी गरीबों के संगठनों को वेंचर कैपिटल सीधा मिल सकता है जिससे वे झोंपड़पट्टियों की समस्याओं के नये और स्थायी समाधान खोजने की अपनी क्षमता दिखा सकें। इन तरीकों की परिभाषा दी जाये तो ये प्रायोगिक ही माने जायेंगे। ये नये विचारों का छोटे पैमाने पर परीक्षण करते हैं और फिर उन्हें बढ़ाने का अवसर दूँदते हैं, जिससे की अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। यह वित्त लम्बी अवधि के ठोस समाधान दूँदने में शहरों की सहायता करता है जिससे वे छोटी अवधि के या एकल पाइलट प्रोजेक्ट के परे काम कर सकें।

FSI – FLOOR SPACE INDEX

This limits the amount you can construct on one site. For eg., if FSI is 2.5, it means on a 1,000 sq. metres plot, you can construct upto 2,500 sq. metres area.

TDR – TRANSFERABLE DEVELOPMENT RIGHTS

is a market mechanism that gives builders an incentive to construct rehab tenements for slum dwellers. For instance, if a builder is constructing rehab tenements on plot A, he has the right to construct additional units on the plot to finance the rehab element of his project. Alternatively, he can finance this construction by selling the TDR so that it can be used for equivalent construction anywhere to the north of the plot.

SRA SCHEME – SLUM REHABILITATION AUTHORITY SCHEME

Under the SRA Scheme, slum dwellers in Maharashtra who can prove they have been living in a slum since 1.1.1995 are eligible for a free 225 sq. metres tenement. Part of the land is used to rehouse existing slum dwellers in multi-storeyed apartments, the remaining is used to build apartments to sell on the open market. In this way free housing for the poor is cross-subsidised.

एफ.एस.आय. – प्लोर स्पेस इंडेक्स

यह सीमित करता है कि एक जमीन पर कितना निर्माण हो सकता है। उदाहरणार्थ, यदि एफ.एस.आय 2.5 है तो इसका अर्थ यह है कि यदि जमीन 1000 वर्ग फुट है तो उस पर आप 2,500 वर्ग फुट तक का निर्माण कर सकते हैं।

टी.डी.आर. – ट्रांसफरैबल डेवलपमेंट अधिकार

ऐसा बाज़ारी तंत्र है जो झोंपड़पट्टीवासियों के लिये पुनर्वसन आवास बनाने के लिये बिल्डरों को बढ़ावा देता है। जैसे, यदि कोई बिल्डर प्लॉट A पर पुनर्वसन आवास बना रहा है, उसे उस प्लॉट पर अतिरिक्त इकाइयाँ बनाने का अधिकार है जिससे वह अपनी परियोजना के पुनर्वसन हिस्से का खर्चा निकाल सके। या वह निर्माण का खर्च टी.डी.आर. बेच कर निकाल सकता है, जो कि प्लॉट के उत्तर में कहीं भी बराबरी के निर्माण के लिये काम में लिया जा सकता है।

एस.आर.ए. योजना – स्लम रीहैबिलिटेशन अथोरिटी योजना

एस.आर.ए. योजना के तहत, महाराष्ट्र के वे झोंपड़पट्टीवासी जो यह सिद्ध कर सकें कि वे 1.1.1995 के पहले से झोंपड़पट्टी में रह रहे हैं, 225 वर्ग मी. के मुफ्त आवास के लिए योग्य हैं। जमीन के कुछ भाग में वहाँ के झोंपड़पट्टीवासियों के लिए बहुमंजिली इमारतें बनती हैं और बाकी जमीन में घर बना कर खुले बाज़ार में बेचे जा सकते हैं। इस तरह गरीबों के मुफ्त आवास क्रॉस-सब्सिडाइज़ हो जाते हैं।





Setting High Standards for Highrise Housing

"OUR'S is a very different community-driven design," said Ravi, site engineer for Oshiwara Project-I, "they've got just one room with no separate living spaces." He was comparing the 225 sq. foot Alliance-designed and built apartments for MUIP-affected households, with neighbouring ones put up by a private builder.

Each Alliance tenement has a separate kitchen, common room, bedroom, toilet and bathroom. The corridors are five feet wide and built to allow in maximum light and breeze. There's an internal courtyard for large gatherings.

For those not in the know, MUIP or the Mumbai Urban Infrastructure Project is a road-widening project undertaken by the Government of Maharashtra, which involves the resettlement of some 30,000 families that lived along the affected roads. In June 2003, the Alliance was given the sole contract for survey and resettlement of all these families.

The Alliance also undertook to construct 800 tenements as part of this project. Construction work was handled by the Alliance's sister-organisation Nirman (SSNS) and financed through bridge funds provided by CLIFF (Community Lead Infrastructure Financing Facility.) Like in other Alliance projects, much of the brickwork, plastering, and painting was taken up by MM contractors.

The Oshiwara project is an important milestone for the Alliance because for the first time it has taken up the challenge to complete such a large project within a short span of time. Federation leaders regularly accompanied project-affected people to view the tenements. Preference of floors is given to people who are not well or are elderly with the rest of the floors and flats assigned by lottery.

Although many communities were not part of the Federation before this project, they subsequently opened savings accounts with MM to pay for increased maintenance costs. As the Alliance stresses, poor, vulnerable families must plan as a collective so they may benefit in the move from informal to formal housing systems.

Oshiwara is just one of the sites that MUIP-affected families will live in. But the hope is that communities, seeing the high – and yet financially feasible – standards of Alliance houses, will make similar quality demands on private developers through MMRDA, the nodal agency coordinating the project.

ऊंची इमारतों के लिए ऊंचे स्तर

"हमारा बहुत अलग समुदाय केन्द्रित डिज़ाइन है" ओशिवारा परियोजना-1 के इंजीनियर रवि का कहना है, "उनके पास सिर्फ एक कमरा है जिसमें अलग अलग रहने की जगह नहीं है।" वो एम.यू.आई.पी. से प्रभावित परिवारों के लिए गठबंधन द्वारा डिज़ाइन की गयी और निर्मित इमारतों की तुलना, पास ही की निजी बिल्डर द्वारा निर्मित इमारतों से कर रहा था।

हर गठबंधन घर में एक अलग रसोई, साधारण कमरा, सोने का कमरा, शौचालय और स्नानघर है। गलियारे पांच फुट चौड़े हैं और पूरी रौशनी और हवा आने देते हैं। बड़ी मीटिंग के लिए अंदर एक चौक है।

जिन्हें पता नहीं है – एम.यू.आई.पी. (मुंबई अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट), महाराष्ट्र सरकार का सड़क चौड़ा करने का उद्यम है, जिसके तहत प्रभावित सड़कों के किनारे रहने वाले परिवारों का पुनर्वसन किया जाएगा। जून 2003 में इन सभी परिवारों के सर्वे और पुनर्वसन का एकल ठेका गठबंधन को दिया गया।

गठबंधन ने इस परियोजना के तहत 800 घर बनाने का भी बीड़ा लिया। निर्माण का काम किया स्पार्क की गैर-लाभ इकाई 'निर्माण' (एस.एस.एन.एस) ने और पैसा आया क्लिफ (कम्यूनिटी लेड इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग फौंडेशन) के ब्रिज फंड से (विस्तार के लिए देखिए पृष्ठ कृ37)। गठबंधन की अन्य परियोजनाओं की तरह, इंटों का, प्लास्टर का और रंग-रोगन का अधिकतर काम महिला मिलन ठेकेदारों ने किया।



गठबंधन के लिए ओशिवारा परियोजना खास महत्वपूर्ण है क्योंकि उसने पहली बार कम समय में इतनी बड़ी परियोजना पूरी करने की चुनौती स्वीकार की है। संगठन के नेता नियमित रूप से परियोजना प्रभावित लोगों के साथ नए घर देखने आते थे। निचली मंज़िलों पर बीमार या बुजुर्गों को प्राथमिकता दी जाती है और बाकी के घरों के लिए लॉटरी निकाली जाती है।

इस परियोजना के पहले कई समुदाय संगठन में नहीं थे लेकिन बाद में उन्होंने महिला मिलन के साथ बचत खाते खोले जिससे बढ़ते रखरखाव के खर्च दे सकें। गठबंधन इस बात पर जोर देता है कि गरीब और निर्बल परिवारों को मिल कर, समुदाय की तरह, योजना बनानी चाहिये – जिससे वे अनौपचारिक से औपचारिक आवास में आने में समन्वय बिठा सकें।

ओशिवारा सिर्फ एक ही जगह नहीं है जहाँ एम.यू.आई.पी. प्रभावित परिवार रहेंगे। पर आशा यह है कि गठबंधन के घरों के उच्च स्तर और उचित दाम देखकर, समुदाय एम.एम.आर.डी.ए के जरिए निजी बिल्डरों से भी ऐसे ही स्तर की मांग रखेंगे। एम.एम.आर.डी.ए इस परियोजना का संचलन कर रहा प्राधिकरण है।



गठबंधन ने ओशिवारा में अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना ली

पड़ोसी देख रहे थे। जब यह स्पष्ट हो गया कि ओशिवारा परियोजना-1 के निर्माण द्वारा बनाए गए 800 घरों का काम ठीक से चल रहा था, तो पास ही की जमीन के मालिक एक और परियोजना लेकर गठबंधन के पास आए।

उनका प्रस्ताव था कि गठबंधन 2000 से अधिक परिवारों के लिए घर बनाए।

मुंबई में गठबंधन की सबसे बड़ी निर्माण परियोजना! वार्ताओं के बाद, अगस्त में मेमोरैंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर हुए, उसके कुछ समय बाद ही नींव का काम शुरू हो गया।

ओशिवारा-2 परियोजना में अतिक्रमण करने वालों में भेसों के तबेले प्रमुख हैं। कुल मिलाकर उस जगह से 372 झोंपड़पट्टीवासियों को चार इमारतों में घर दिए जाएंगे। कई तबेलों को हटाना पड़ेगा और उस जगह पर स्थित तीन प्रिंटिंग प्रेस वालों के साथ बातचीत चालू है कि वे अपनी जमीन के बदले इन बहुमंजिली इमारतों में मुफ्त जगह ले लें। क्योंकि निजी जमीन के बड़े हिस्से पर अतिक्रमण हो चुका है, मालिक संगठन के साथ भागीदारी करना



Alliance Takes Up Most Ambitious Project Yet at Oshiwara

THE neighbours were watching. When it was clear that the Nirman-constructed Oshiwara Project-I of 800 households was going ahead smoothly, the landowners of the adjoining site approached the Alliance with an even more ambitious project.

Their proposal was for the Alliance to build tenements for over 2000 households – the Alliance's largest construction project in Mumbai! Discussions led to a Memorandum of Understanding being signed in August and foundation work began shortly after.

In what is named Oshiwara II, *tabelas* or buffalo sheds figure prominently among the encroachers. In all, 372 slum dwellers on site will be given tenements in four buildings, many *tabelas* need to be shifted, and negotiations are underway with three printing presses on site to exchange their land for free space in new multi-storied buildings.

Since large parts of private land have been encroached upon, the landowners are keen on partnering with the Federation which can negotiate with residents who have encroached the space. This is one of the Federation's key strengths: the ability to negotiate with slum dwellers on site, and protect their interests, while simultaneously taking into account the other's point of view.

Problems regardless, work is today proceeding apace on six of the planned 24 buildings at Oshiwara II. Three contractors have taken up construction while sub-contracts for brickwork, painting and plastering will be given to community contractors from NSDF. The contractors have built transit tenements for their labour, provided a medical dispensary, and reserved space for a creche for the labourers' children – all requirements set down by the Alliance.

The Oshiwara projects show that the Alliance is clearly setting a trend. They demonstrate to landowners and government authorities and, what's more, to financial institutions, that the Alliance makes a reliable development partner. Branch officials from NHB and ICICI who have been closely following the Alliance's work at Oshiwara have agreed to give a large loan for this construction.



Oshiwara / ओशिवारा

चाहते हैं क्योंकि वही इस समस्या का सामना कर सकता है। यही संगठन की मुख्य शक्ति है – जगह पर रहने वाले झोंपड़पट्टीवासियों से बातचीत की क्षमता, उनके हितों की रक्षा करना और साथ ही सामने वाले के नजरिए को भी समझ लेना। कठिनाईयां हैं, फिर भी आज ओशिवारा-2 में प्रस्तावित 24 में से 6 इमारतों पर काम जोरों से चल रहा है। तीन ठेकेदारों ने निर्माण काम लिया है जब कि इंटों के काम, रंग-रोगन और प्लास्टर के काम के छोटे ठेके एन.एस.डी.एफ. के समुदाय ठेकेदारों को दिए जाएंगे। ठेकेदारों ने अपने मजदूरों के लिए अस्थायी निवास बनाए हैं, एक दवाखाना बनाया है और मजदूरों के बच्चों के लिए बाल-वाड़ी की जगह अलग रखी है। ये गठबंधन द्वारा प्रस्तुत जरूरतें हैं। ओशिवारा परियोजनाएं साफ दिखाती हैं की गठबंधन नई विचारधारा ला रहा है। इन्होंने जमीन मालिकों, सरकार और वित्तीय संस्थाओं को दिखाया है कि गठबंधन भरोसेमंद भागीदार है। ओशिवारा में गठबंधन के काम को निकट से देखने वाले आई.सी.आई.सी.आई. के अफसरों ने इस निर्माण के लिए एक बड़ा ऋण देने की मंजूरी दे दी है।



PSDF Opens Doors for Homeless



AUGUST 2004, the Federation approved a housing loan of Rs. 6,96,000 or Rs. 24,000 each for 29 members of the Pondicherry Slum Dwellers Federation. These members live in a slum called Swamipillaithotam, which has been affected by a road-widening project.

Although 134 families live in the slum, the government has agreed to resettle only those families who can prove they own their structure. Those that rent their homes – even if they have been living there for decades – have to pay Rs. 24,000 to purchase land. Fortunately for these families, a nearby factory has agreed to loan this amount to its workers from the slum.

However, 29 members of the PSDF benefit neither from the government's plans (because they rent rooms) nor from the factory (since they do not work there). For them, the Federation is the only route to loans. They have been with the PSDF for the last five years and have collected Rs. 3000 in their house savings accounts which they will offer as down payment towards the loan.

Fortunately, since it is the 100th anniversary of local leader Kamraj, under a special Kamraj Yojna, Rs.40,000 is being offered to each slumdweller who wants to build a home and has the necessary land *patta* (deed). By loaning money to these families to buy land, the Federation will ensure that they can take advantage of the Kamraj Yojana to build new homes for themselves.

पोंडिचेरी

पी.एस.डी.एफ ने बेघरों के लिए खोले दरवाजे

अगस्त में संगठन ने पोंडिचेरी झोंपड़पट्टीवासी संगठन के 29 सदस्यों के लिए रु. 6,96,000 या प्रति व्यक्ति रु. 24,000 के आवास ऋण की मंजूरी दी। ये सदस्य स्वामीपिल्लैथोटम नाम की झोंपड़पट्टी में रहते हैं जो कि सड़क चौड़ी करने की परियोजना से प्रभावित हुई है।

हालांकि झोंपड़पट्टी में 134 परिवार रहते हैं, सरकार सिर्फ उन्ही परिवारों का पुनर्वसन करेगी जो सिद्ध कर सकें कि वे अपने झोंपड़े के मालिक हैं। जो लोग किराए से रह रहे हैं – चाहे वे दसियों सालों से रह रहे हैं – उन्हें जमीन खरीदने के लिए रु. 24,000 चुकाने होंगे। इन परिवारों के भाग्य से, पास ही की एक फैक्टरी ने इस झोंपड़पट्टी के अपने यहां काम कर रहे मज़दूरों को यह राशि ऋण स्वरूप देने की मंजूरी दी है। लेकिन पी.एस.डी.एफ. के 29 सदस्य ऐसे हैं जिन्हें न तो सरकार से लाभ है (क्योंकि वे किरायदार हैं) और न ही फैक्टरी से (क्योंकि वे वहां काम नहीं करते)। उनके लिए संगठन ही ऋण लेने का एकमात्र जरिया है। वे लोग पी.एस.डी.एफ. के साथ पिछले पांच वर्षों से हैं और अपने आवास बचत खातों में रु. 3000 जमा कर चुके हैं। यह राशि वे ऋण के लिए अग्रिम राशि के रूप में दे रहे हैं।

सौभाग्यवश, स्थानीय नेता कामराज की सौवीं जयंती है और एक विशेष कामराज योजना के तहत ऐसे हर झोंपड़पट्टीवासी को, जिसके पास जमीन का पट्टा है और जो घर बनाना चाहता है, रु. 40,000 दिये जाएंगे। ऐसे परिवारों को जमीन खरीदने के लिए ऋण देकर संगठन पक्का करना चाहता है कि वे अपने घर बनाने में कामराज योजना का लाभ उठा सकेंगे।



PSDF secured land for its members who had been excluded from a government relocation program. Above, the Federation also gave loans to help people buy land and begin constructing their new homes.

पी.एस.डी.एफ.ने अपने उन सदस्यों के लिये जमीन पक्की की जिन्हें सरकारी पुनर्वसन कार्यक्रम में नहीं रखा गया था। ऊपर, गठबंधन ने लोगों को जमीन खरीद कर अपने नये घरों का निर्माण कार्य शुरू करने के लिये ऋण भी दिये।



अखिल भारतीय झोंपड़पट्टीवासियों का ब्याज पर संवाद

'च'लो मानखुर्द' इस वर्ष का नारा था सबको राष्ट्रीय झोंपड़पट्टीवासी संगठन के अधिवेशन में बुलाने का और अक्टूबर 1 से 3 के बीच मानखुर्द में हुए एन.एस.डी.एफ. के पांचवें वार्षिक अधिवेशन में आ कर पूरे देश के, संसार के और मुंबई शहर के झोंपड़पट्टीवासियों ने इसका उत्तर दिया। केवल मुंबई से ही 20000 लोग आये। उत्तर प्रदेश से ले कर तामिलनाडु के बीच आठ राज्यों के 42 शहरों से 400 प्रतिनिधि आये। विदेशों से भी 50 से अधिक प्रतिनिधि आये।

बातचीत के दो प्रमुख मुद्दे थे। सभी संगठित राज्यों में से मिल कर नेताओं की केन्द्रीय समिति का चुनाव और हर शहर के लक्ष्यों और काम के बारे में वार्षिक रिपोर्ट। तीनों दिनों में से हर दिन ही खूब बातचीत हुई। पहले दिन के सत्र में ब्याज के मामले पर हुई आंतरिक चर्चा बहुत महत्वपूर्ण थी। जब से बचत और ऋण का कार्यक्रम शुरू हुआ है, संगठन ऋण पर एक प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज लेता है पर बचत पर कोई ब्याज नहीं देता। जब कई सदस्यों ने इस नीति पर प्रश्न उठाया तो नेताओं ने इसे चर्चा के लिये सामने कर दिया।

तीन महिला मिलन नेताओं—पुणे की सविता सोनावने, बैंगलोर की बी.एल. मेरी और उड़ीसा की संजुक्ता ने उत्साहित वाद विवाद की अध्यक्षता की। अंततः लोगों ने ब्याज देने के विरुद्ध निर्णय लिया क्यों कि उस पैसे से महिला मिलन के कार्यकारी खर्चे निकलते हैं, और क्यों कि वो अब बचत इकट्ठी करना और ऋण देना ही नहीं बल्कि समुदाय के कल्याण के लिये कई और काम भी करते हैं।

जिससे की सभी लोग सारी गतिविधियों को ठीक से समझ पायें एक साथ तामिल, मराठी, तेलगु, कन्नड़, अंग्रेजी और उड़िया भाषाओं में अनुवाद चल रहे थे। जो अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि अंग्रेजी नहीं समझ सकते थे उनके लिये नेपाली भाषा

इंडोनेशिया, स्वाहिली, केनिया एवं यूगांडा और खोसा और जुलू दक्षिण अफ्रीका की भाषाओं में अनुवाद था। स्पष्ट रूप से संस्कृतियों और भाषाओं का मिश्रण! पर एन.एस.डी.एफ. के लिये ऐसा हमेशा ही रहा है और हमेशा रहेगा। >



For the huge turnout at the NSDF's 5th National Convention, there was simultaneous translation in six Indian languages and five international ones!

एन.एस.डी.एफ. के पांचवें राष्ट्रीय अधिवेशन में बड़ी संख्या में आये लोगों के लिये छः भारतीय और पांच अंतरराष्ट्रीय भाषाओं में हाथों हाथ अनुवाद चल रहा था!

All-India Slum Dwellers Debate Interest Issue

'C'HALO MANKHURD' – was the roundup call of the National Slum Dwellers Federation's national convention this year. And from across the country, the world and the city of Mumbai, slum dwellers responded as they streamed into Mankhurd for NSDF's Fifth Annual Convention, Oct. 1 to 3. There were 20,000 participants from Mumbai alone. More than 400 delegates came from 42 cities in eight states ranging from UP in the north to TamilNadu in the south, besides 50 and more delegates from abroad.

The two main issues on the agenda were: Electing a central committee of leaders from all the federated states, and to present each city's annual report of targets and output.

Each of the three days was packed with discussions, including an important internal debate on the issue of interest during the first day's session. Since the savings and credit programme began, federations have been charging 1% interest a month on loans, but not distributing any interest on savings. When many members questioned this policy, the national leadership threw it open for nationwide discussion.

Three Mahila Milan leaders, Savita Sonawne from Pune, B.L. Mary from Bangalore and Sanjukta from Orissa, chaired the enthusiastic debate. Ultimately the people decided against interest distribution because that money would help cover operation costs of the MM whose functions went beyond savings-collection and loan-disbursing to taking care of all aspects of community welfare.

To make sure that everyone could understand all the happenings clearly, there were simultaneous translations in Tamil, Marathi, Telugu, Kannada, English and Oriya. For the international delegates who couldn't understand English, there were translations in Nepalese, Bhasa (Indonesia), Swahili (Kenya and Uganda) and Xhosa and Zulu (South Africa). Clearly a polyglot of cultures and languages, but that's how its always been and will be for the NSDF...

Sab Sambhav Hai

Traditionally, on the second day of the Convention, NSDF invites government officials to meet the slum communities from all over the country so both may appreciate each other's contribution towards improving the lives of the urban poor. >



Taking Charge



Federation children entertain the audience at the convention. Their song is in praise of police panchayats.

गठबंधन के बच्चे अधिवेशन में लोगों का मनोरंजन करते हुए। उनका गाना पुलिस पंचायतों की बढाई कर रहा है।



> This year the Chief Guests were Maharashtra Director General of Police K.K. Kashyap and Mumbai Police Commissioner of Police Anami Roy. Two very senior officials – ex-Chief Secretary of Maharashtra D.M Sukhtankar and ex-Director General of the Maharashtra Anti-Corruption Bureau S.S.Puri – were also present.

In a speech that touched everyone with its commitment and passion, Mr. Roy, who pioneered the community policing scheme in Pune and is now a committed supporter of the Alliance, said it was critical for the poor and the police to begin to change their stereotypes about each other and work together. “Why should the poor always be blamed for crimes they have not committed simply because they are poor? I want to work for a situation where a poor man or woman is not frightened before he/she enters a police station. Wherein they know they will get justice.”

Mr. Kashyap promised to support the NSDF as well as the police force in setting up similar Police Sahayak schemes throughout Maharashtra State.

Of all the events in the National Convention, this is the most special – for there are no other events or platforms where the poor and city officials come together in this manner. Indeed, the very air seemed to vibrate as federations from across the country and world, visitors, officials – all recognized the power of a strong and organized collective. *Sab Sambhav Hai!* (Everything is possible) was the slogan ringing in all hearts.

K.K. Kashyap, then DIG of Maharashtra Police, was a Chief Guest at the NSDF convention along with Mumbai Police Commissioner A.N. Roy.

के.के.कश्यप, महाराष्ट्र पुलिस के तत्कालीन डी.आई.जी., एन.एस.डी. एफ. अधिवेशन में मुंबई पुलिस कमिश्नर ए.एन.रॉय के साथ मुख्य अतिथि थे।



सब संभव है

> पारंपरिक रूप से अधिवेशन के दूसरे दिन, एन.एस.डी.एफ., सरकारी अफसरों को देश के झोंपड़पट्टी समुदायों से मिलने आमंत्रित करता है जिससे शहरी गरीबों के जीवन सुधारने के एक दूसरे के योगदान का वे आभार मान सकें। इस वर्ष मुख्य अतिथि थे दो बहुत वरिष्ठ अधिकारी, मुंबई के पुलिस आयुक्त ए.एन.रॉय और महाराष्ट्र के पुलिस महानिरीक्षक के.के.कश्यप। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव डी.एस. सुखतंकर और महाराष्ट्रके भ्रष्टाचार विरोध विभाग के पूर्व महानिरीक्षक एस.एस.पुरी भी उपस्थित थे।

श्री रॉय के भाषण ने अपनी प्रतिबद्धता और भावना से सबको छू लिया। श्री रॉय, जिन्होंने पुणे में समुदाय पुलिस योजना प्रारंभ की अब गठबंधन के पक्के मित्र हैं। उन्होंने कहा कि बहुत आवश्यक है की गरीब और पुलिस एक दूसरे के बारे में पूर्वाग्रह छोड़ दें और मिल कर काम करें। हमेशा गरीबों को ऐसे अपराधों के लिये क्यों दोषी ठहराया जाता है जो उन्होंने किये ही नहीं? सिर्फ इसलिये की वे गरीब हैं। मैं ऐसी स्थिति के लिये काम करना चाहता हूँ जहां कोई गरीब पुरुष या महिला पुलिस स्टेशन में आने में न डरे, जहां पता हो कि उन्हें न्याय मिलेगा।

श्री कश्यप ने वादा किया की वे एन.एस.डी.एफ. और पुलिस का महाराष्ट्र राज्य में ऐसी अन्य पुलिस सहायक योजनाएँ लागू करने में समर्थन देंगे।

राष्ट्रीय अधिवेशन के सभी कार्यक्रमों में से यह सबसे विशिष्ट है क्यों कि और कोई भी कार्यक्रम या मंच नहीं है जहां गरीब और नागरी अधिकारी इस तरह मिल कर आते हैं। वास्तव में वहां की हवा तक में स्फूर्ति थी। जब देश के संगठन, प्रवासी और अफसर मिल कर शक्तिशाली और संगठित समुदाय की ताकत को पहचान रहे थे सभी के दिलों में नारा गूंज रहा था – सब संभव है!



ये आपने कैसे किया

लल्लूभाई कम्पाउंड देखने गये प्रतिनिधियों के लिये तीसरा दिन बड़ा यादगार था। यहां एन.एस. डी.एफ. की देखरेख में मुंबई शहरी यातायात और मुंबई संसाधन परियोजनाओं (एम.यू.टी.पी., एम.यू.आई.पी) से प्रभावित मुंबई के झोंपड़पट्टी और फुटपाथ के 10,000 परिवारों का पुनर्वसन होगा। दस हजार नये रंग रोगन किये हुए घर, दोपहर की धूप में चमकते हुये वास्तव में बड़े प्रभावी थे। साथ ही उन सैकड़ों दुकानदारों के लिये बड़ा सा व्यवसायिक संकुल था जिनके व्यापार पर पुरानी जगह से हटने के कारण असर पड़ेगा। लोग उत्साह से घरों में जा जा कर देख रहे थे। बाहर आ कर खुली जगहों और गलियारों की प्रशंसा कर रहे थे और फिर जोकिन से प्रश्न पूछ रहे थे – आपने कैसे किया? घर कौन बना रहा है? आप कैसे कहां से लाये?

जोकिन ने एस.आर.ए. झोंपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण के तहत झोंपड़पट्टीवासियों के वैकल्पिक आवास के अधिकार के बारे में एवं लोगों को पुनर्वसन के लिये तैयार करने की एन.एस.डी.एफ. युक्तियों के बारे में बताया। उनका सीधा संदेश था— तुम्हें विकास योजनाओं का विरोध करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अच्छी सड़कें, रेलवे और हवाई अड्डे शहर को प्रभावी बनाते हैं। साथ ही यह आवश्यक है कि यह पहचान जायें की इन परियोजनाओं की सफलता के लिये उन्ही गरीबों का योगदान जरूरी है जिन्हें यह जगह से उखाड़ती हैं। सूक्ष्म तौर पर, समाधान खोजते समय गरीबों को साथ में ले कर चलना चाहिये जिससे वे शहर, परियोजना और गरीब, सभी के लिये काम कर सकें।

How Did You Do It?

A VISIT to Lallobhai Compound on the third day proved highly memorable for delegates. Here, assisted by NSDF, 10,000 families from slum and pavement settlements around Bombay who have been affected by the Mumbai Urban Transport and Mumbai Urban Infrastructure Projects (MUTP, MUIP) are being resettled.

Ten thousand new, freshly painted flats, shining in the afternoon sun was an awesome sight indeed. Besides, there was the imposing commercial complex for hundreds of shopkeepers. People eagerly flocked through the flats, stepping out only to admire the layout of open spaces and corridors, then accosting Jockin with questions, 'How did you do it?' 'Who's building the houses?' 'Where do you get the money?'

Jockin explained slum dwellers' rights to alternate accommodation under the SRA (Slum Rehabilitation Authority) Scheme and NSDF strategies to prepare people for resettlement. His message was direct, "You don't need to oppose development projects because better roads, railways and airports make the city more efficient. At the same time, it is critical to recognize that the success of these projects is rooted in the participation of the very people it affects. In short, the poor must be involved in designing solutions that work for the project, the city, and the poor."

Left, Ugandan officials were keen to understand how resettlement proceeded. Below, 10,000 houses were built at Lallobhai Compound in Mankhurd for families affected by MUTP and MUIP projects.

बायें, यूगांडा के अफसर पुनर्वसन का तरीका समझने के लिये उत्सुक थे। नीचे, एम.यू.टी.पी. एवं एम.यू.आई.पी. परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों के लिये मानखुर्द स्थित लल्लूभाई कम्पाउंड में 10,000 घर बनाये गये।

World Bank team and MMRDA officers visit Lallobhai

वर्ल्ड बैंक का दल और एम.एम.आर.डी.ए. के अफसर लल्लूभाई गये।



Community Contractors Take On Jobs Nationwide

THE subcontract for the construction of Bharat Janata tenements (at Dharavi in Mumbai) has been given to a company set up by three community contractors – Muthu, Shanmuganand and Usman. Both Muthu and Shanmuganand have supervised the construction of five buildings in the neighbouring Rajiv Indira society and also built several community toilets. Confident that they now have the skills to manage a large project, they applied to the committee of Nirman (SSNS) and the Bharat Janata Cooperative Society for its construction contract – and got it.

They are part of a new and expanding tribe of community leaders who are taking on construction all over the country. A pair of Mahila Milan leaders – Meena Ramani and Lizbeth Naidu – have together built six community toilets at various sites across Mumbai and have recently completed a 40-seater toilet block in Hyderabad (AP).

Then there's Rehmat Sheikh, a veteran Mahila Milan leader who's become famous throughout the Federation for her many construction contracts. She hires older boys from Sadak Chaap (the street children's federation) as her labourers and has built '5 star' toilets all over the city. Right now, she's in the midst of completing the construction of a three-storey apartment building in Pune.

The way the community contractors have gone about building their own experience is like this: First, assist on the construction of a community toilet, use all the knowhow gained there to take on the next toilet contract single-handedly – only then graduate to larger housing projects.

Since many of the community contractors need initial start-up capital, the Alliance provides both technical and monetary support for community contractors to become financially independent.

समुदाय ठेकेदारों ने देश भर में काम लिया

मुंबई की धरावी स्थित इमारत भारत जनता के निर्माण का उप-ठेका तीन समुदाय ठेकेदारों द्वारा बनायी गयी कम्पनी को मिला है। मुत्थु, और क्षणमुगानंद दोनों ने पास की राजीव-इंदिरा सोसायटी की पांच इमारतों के निर्माण की देखरेख की है और कई समुदाय शौचालय भी बनाये हैं। इस आत्मविश्वास के साथ की अब वे बड़ी परियोजना का संचालन कर सकते हैं, उन्होंने निर्माण (एस.एस.एन.एस.) और भारत जनता सहकारी संस्था को निर्माण ठेके के लिये अर्जी दी – और ठेका मिल गया।

वे देश भर में निर्माण ठेके लेने वाले में से हैं। महिला मिलन की दो नेताओं मुंबई की अलग अलग जगहों में छः में उन्होंने हैदराबाद, आं.प्र. में एक 40

और फिर है रहमत शेख, वरिष्ठ प्रसिद्ध है। अपने कई निर्माण ठेकों के मजदूर रखती है ओर पूरे शहर में '5 सितारा' शौचालय बना चुकी है। अभी वह पुणे में एक 3 मंजिली रिहायशी इमारत का निर्माण पूरा करने में लगी है।

समुदाय ठेकेदारों ने अपना अनुभव इस तरह से बढ़ाया है – पहले सामुदायिक शौचालय के निर्माण में सहायक बनो। वहां से सीखे हुए सारे काम की जानकारी से अगला शौचालय ठेका अकेले लो और उसके बाद ही बड़ी आवास परियोजनाएं हाथ में लो। क्योंकि कई समुदाय ठेकेदारों को प्रारंभिक वित्त की जरूरत होती है, गठबंधन समुदाय ठेकेदारों को तकनीकी और वित्तीय सहारा देता है जिससे वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो कर काम कर सकें।



New Directions

समुदाय नेताओं के नये और बढ़ते गुट – मीना रमानी और लिज्बेथ नायडू ने समुदाय शौचालय बनाये हैं और हाल सीट का शौचालय पूरा किया है।

महिला मिलन नेता जो पूरे संगठन में लिये वो बड़े सड़क छाप लडकों को

Sense & Incense

KOLAR GOLD FIELDS used to be a mining town, but now almost all its residents travel to neighbouring Bangalore for work.

In an innovative effort to support small-scale livelihood activities within KGF, the Federation initiated the Agarbatti (or incense sticks) Fund. Although a number of people, particularly women, wanted to be involved in this home-based income-generating activity, they could not afford the start-up capital required to buy the wooden stand with which sticks are rolled.

The Federation came to the rescue – using community labour they got the stands made cheaper, then loaned members the money to buy the stands... Not only are many more agarbattis being rolled now, the working women are on a roll too!!





July '04, MM leaders from Mumbai were invited to inaugurate the Bangalore regional conference.

जुलाई 04 में मुंबई महिला मिलन की नेताओं को बैंगलोर प्रादेशिक कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करने के लिये आमंत्रित किया गया।

नेताओं की अगली पंक्ति विकसित करना



नियमित आदान-प्रदान द्वारा, पुराने और अधिक विकसित संगठनों के नेता समुदाय और शहरी स्तर पर उभरते

नेताओं की पहचान करते हैं और उन्हें बढ़ती जटिलता के मुद्दों से निपटने में सहायता देते हैं। वे ये भी ध्यान रखते हैं कि महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहन और संरक्षण

दिया जाये।

पिछले दो दशकों में, नेताओं की एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक जानकारी, अनुभव और युक्तियाँ बांटने का यह सहज और अनौपचारिक तरीका एन.एस.डी.एफ. को सबसे तेज और प्रभावशाली लगा है।

पिछले कुछ वर्षों में, स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय समुदायों की गतिविधियाँ और अधिक करने की बढ़ती मांग को ले कर एन.एस.डी.एफ. ने अपने तरीकों को औपचारिक रूप देना शुरू किया है। एन.एस.डी.एफ. के '04 के राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रादेशिक समितियाँ बनायी गयीं और शहरी नेताओं ने अपने अपने इलाकों से दो दो नेता चुने। कुल 70 नेता, जिसमें अधिकतर महिलायें थी, चुने गये। दो महिनों बाद एक राष्ट्रीय कमेटी जिसमें पांच नेता – तीन महिला मिलन से एवं दो संगठन से, नेता चुने गये। प्रादेशिक समितियाँ हर महिने मिलेंगी और राष्ट्रीय कमेटी हर कुछ महिनों में।

आंदोलन के दूरदृष्टा ए.जोकिन संगठन को परामर्श देते रहते हैं और उन्हें स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के लिये प्रोत्साहित करते हैं। हालांकि वे लगातार नये तरीके अपनाते हैं और बड़े पैमाने के शहर और राष्ट्र स्तर के सौदे करवाते हैं, वे अब जानबूझ कर अपना ज्यादा समय एस.डी.आई. को शक्तिशाली बनाने में लगा रहे हैं और शहरी गरीबी पर अंतरराष्ट्रीय नीति प्रवर्तन और उसकी वकालत में अधिक लिप्त हो रहे हैं।

समझ और सुगंध

को लार स्वर्ण क्षेत्र पहले एक खनन शहर था, पर अब वहां के लगभग सभी रहिवासी काम के लिये पड़ोस के बैंगलोर जाते हैं।

कोलार स्वर्ण क्षेत्र में ही लघु जीवीका गतिविधियाँ चलाने के लिये गठबंधन ने एक नवीन अगरबत्ती निधि शुरू की है। हालांकि काफी लोग, विशेष रूप से महिलायें, इस घरेलू कमाई के तरीके को अपनाना चाह रहे थे, उनके पास प्रारंभिक पूंजी नहीं थी की अगरबत्तियाँ बेलने के लिये लकड़ी के स्टैन्ड खरीद सकें।

संगठन ने उनकी सहायता की – समुदाय के कारीगरों से उन्होंने सस्ते में स्टैन्ड बनवाये, फिर उन्होंने सदस्यों को ऋण दिये जिससे वे स्टैन्ड खरीद सकें।न केवल खूब अगरबत्तियाँ बन रही हैं, वहां की महिलायें भी अब खूब आगे बढ़ रही हैं।



Developing the Next Line of Leaders

THROUGH regular exchanges, older and more mature Federation leaders identify and mentor emerging settlement-level and city leaders to tackle increasingly complex issues. They also make sure that women's participation is encouraged and nurtured.

For the past two decades or so, the NSDF has found this organic and informal method the fastest and most efficient way to transfer knowledge, experience and strategies from one generation of leaders to the next.

However, the last few years, with increasing demands from local and global communities to scale up activities, NSDF has begun to formalise its structures. Regional committees were formed up at NSDF's National Convention '04 with city leaders voting two leaders each from their area. In all, 70 leaders, the majority of who were women, were appointed.

Two months later, a national committee – comprising five leaders, three from Mahila Milan and two federation leaders – was elected. Regional committees will meet monthly, and the national committee, every few months.

A. Jockin, visionary of the movement, continues to advise federations, at the same time encouraging them to take more decisions independently. Whereas he continues to constantly innovate and broker large scale city and state-level deals, he is consciously spending more time strengthening SDI and getting involved in international policy-making and advocacy on urban poverty.



New Leaders Emerge in Smaller Feds

WHEN Mohan Sundaram and a team of the Pondicherry Slum Dwellers Federation visited Kanchipuram in August 2004, it was an important milestone for the PSDF. Although Pondicherry has taken care of federations in neighbouring Karaikal and Cuddalore, this was their first independent visit to a city with the explicit purpose of guiding a younger federation. It revealed the confidence the Tamil Nadu and National Federations had in these leaders.

In Maharashtra, Pimpri has also emerged as a confident regional leader, capable of mentoring newer feds. They have regular exchanges with communities from Sangli, Ahmednagar and Nasik to help them build their Mahila Milans, strengthen their savings systems, and gradually introduce them to key federation tools.

This ever expanding cadre of community leaders is the cornerstone of the federation process, with more experienced leaders guiding new ones who bring in fresh ideas, energy and drive.

If it's Good Enough for Officers...

WHEN Dr. Srivastava from Delhi's Centre for the Study of Developing Societies (CSDS) visited Orissa in June to evaluate the Alliance's work on behalf of funding agency Sida, he was visibly impressed by the Mahila Milan leaders and their work. He was also keen on finding out on what it meant to the women to be part of a large collective.

Naturally, one of the main issues that came up in this connection was that of domestic violence. Not an easy topic to discuss, but some MMs spoke forthrightly of the ways they coped. "Because I am connected to this organization, I have the confidence to deal with issues in my home," said one woman. "If I can talk to a big officer like you, I naturally have the confidence to talk back to my husband and mother-in-law at home!" said another.

A highly repeatable story comes from Rasulgarh, where the Alliance's first housing construction project in Orissa is underway. Nearly all the men in the settlement get drunk regularly, and a large proportion of them beat their wives. >

छोटे संगठनों में उभरे नेता

जब मोहन सुंदरम और पॉंडीचेरी झोंपड़पट्टीवासी संगठन का एक दल अगस्त 2004 में कांचीपुरम गया तो यह पी.एस.डी.एफ. के लिये एक महत्वपूर्ण घटना थी। हालांकि पॉंडीचेरी पड़ोसी करइकल और कडलूर के संगठनों का ध्यान रखता है, किसी दूसरे शहर में (अपने से छोटे संगठन का मार्गदर्शन करने के उद्देश्य से) यह उनकी पहली यात्रा थी। इसने दिखाया कि इन नेताओं पर तामिलनाडु और राष्ट्रीय संगठन को कितना भरोसा है।



Taking Charge

महाराष्ट्र में पिंपरी भी एक आत्मविश्वास वाले प्रादेशिक नेता के रूप में उभरा है जो नये संगठनों को सहारा दे सकता है। उनका सांगली, अहमद नगर और नासिक के समुदायों के साथ नियमित रूप से आदान-प्रदान होता है जिसके कि वे अपने महिला मिलन बना सकें, बचत योजनायें मजबूत कर सकें और धीरे धीरे अन्य संगठन तरीकों से परिचित हो सकें।

समुदाय नेताओं का यह सतत् बढ़ता दल ही संगठन प्रक्रिया की नींव है। यहां अधिक अनुभवी नेता, नये नेताओं का मार्गदर्शन करते हैं और नये नेता संगठन में ताजे विचार, उर्जा और शक्ति लाते हैं।



Pimpri MM leaders and social worker Pushpa Shankar discuss plans for Pimpri Federation for the coming year.

पिंपरी म.मि. नेता और समाज सेविका पुष्पा शंकर, पिंपरी संगठन की अगले वर्ष की योजनाओं पर चर्चा करते हुए।

यदि यह अफसरों के लिये अच्छा है तो...

दिल्ली के सेंटर ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ के वरिष्ठ अध्ययनकर्ता डा. श्रीवास्तव गठबंधन के काम का मूल्यांकन करने जून में दाता एजेंसी सीडा की ओर से उड़ीसा गये। वे महिला मिलन नेताओं और उनके काम से बहुत प्रभावित हुए। वे यह पता करने के लिये भी उत्सुक थे की महिलाओं के लिये किसी बड़े समुदाय का भाग होने का क्या मतलब है।

स्वाभाविक रूप से इस विषय में सामने आया एक प्रमुख मुद्दा था घरेलू मारपीट का। यह बातचीत का सरल विषय नहीं है। पर कुछ महिला मिलन महिलाओं ने इसका सामना करने के बारे में खुल कर बात की। "क्यों कि मैं इस संगठन से जुड़ी हूँ, मुझमें अपने घर में होने वाले मुद्दों से निपटने का आत्मविश्वास है," एक महिला ने कहा। "यदि मैं आप जैसे बड़े अफसर से बात कर सकती हूँ, तो स्वभाविक है, मैं घर में अपने पति और सास को जवाब दे सकती हूँ," दूसरी ने कहा।

रसूलगढ़ से बड़ी रोचक कहानी आयी है। यहां उड़ीसा में गठबंधन की पहली आवास योजना चालू है। बस्ती के लगभग सारे पुरुष नियमित रूप से नशे में धुत्त हो जाते हैं और उनमें से काफी अपनी पत्नियों को पीटते हैं। पर जब एक महिला मिलन नेता के पति ने गुट की बचत चुरा कर शराब पर उड़ा दी, तो महिलाओं ने कुछ करने का निश्चय किया।

अगली रात जब वो आदमी हमेशा की तरह धुत्त घर आया, उसका सामना हुआ गुस्से में भरी महिलाओं से। उन्होंने जम के उसकी पिटाई की और फिर गले में शर्मनाक पट्टी लटका के उसे पूरी बस्ती में घुमाया। उन्होंने वादा किया कि हर बार वो पी कर आयेगा तो इसी तरह से बेइज्जत करेंगी।

उसने पीना तो नहीं छोड़ा पर फिर से कोई समस्या पैदा नहीं की। हालांकि गुट को अपनी बचत फिर से करनी पडी, इस अनुभव ने साथ काम करने के उनके निश्चय को और भी पक्का कर दिया। >



> “ये चावल के जैसे हैं”, एक महिला नेता ने बताया कि किस प्रकार सदस्यों का आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ता है। “जब आप उन्हें आग पर चढ़ाते हैं तो वो एकदम से नहीं पकते। आप को थोड़ी देर इंतजार करना पड़ता है।”



MM leaders from Cuttack (Orissa). Said one veteran, “Members gradually gain confidence in themselves. It’s like rice, it doesn’t get cooked immediately... the water has to boil.”

कटक (उड़ीसा) की महिला मिलन नेता। पुरानी सदस्या ने कहा, “सदस्यों को धीरे धीरे अपने ऊपर आत्मविश्वास हो जाता है।”

एक शक्तिशाली कनेक्शन

यह एक दूसरी सफलता कि कहानी है जिसे उड़ीसा महिला मिलन ने होमलेस इंटरनेशनल के मालकॉम जैक और स्पार्क की देविका को सुनायी।

जब भुवनेश्वर की एक झोंपड़पट्टी की महिला मिलन नेता अपने स्थानीय कोरपोरेटर के पास बिजली का कनेक्शन मांगने गयी उसे लौटा दिया गया। राजनेता को कोई रुचि नहीं थी कि किसी गरीब अनपढ़ औरत से बात करे जो उसके किसी काम की नहीं है। पर उसने कोशिश नहीं छोड़ी। अपने समुदाय की कुछ महिलाओं के “आप हाल ही में मुंबई और पुणे गये को देखने?” उसने पूछा, “और मैंने ने बात मानी। “ठीक है, मैं भी उसी सदस्य हूँ। हमें यहां बिजली के करेंगे?” महापौर ने कोरपोरेटर को लिये कहा। महापौर ने खुद बुलाया इस बात से आश्चर्यचकित कोरपोरेटर ने महिला मिलन नेता को अगली शाम अपने घर बुलाया। उसे बहुत गुस्सा आया। आखिर, सब को पता है कि कोई औरत किसी अजनबी अदमी के घर देर रात को नहीं जाती। इसकी जगह, अगली सुबह अपनी झोंपड़पट्टी की दूसरी दस महिलाओं को साथ लिये, बिना किसी घोषणा के, वो कोरपोरेटर के घर पहुंच गई। कोरपोरेटर को अचंभा हुआ पर उनसे इज्जत से मिला।



“बैठिये और मेरे साथ नाश्ता करिये, मुझे पता नहीं था की आप महापौर को जानती हैं। बिजली मांगने के लिये उनके पास जाने की क्या जरूरत थी? मैं तो देने ही वाला था।” जब झोंपड़पट्टी में बिजली आयी सभी महिला मिलन के प्रति बहुत आभारी थे। जैसे की कहानी बताती है, किसी अकेले नेता या अकेले समुदाय के लिये चाहे वे संगठित क्यों न हों, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रारंभिक वर्षों में गरीबों के लिये साधन उपलब्ध कराने में उन्हें बड़े जन आन्दोलनों की सहायता मिले।

> But when the husband of one of the MM leaders stole the group’s savings and spent it on alcohol, the women decided to take action.

Next night, when the man returned home, drunk as usual, he was confronted by a group of very angry women. They gave him a sound beating, then paraded him through the colony, wearing an embarrassing sign around his neck. And promised to publicly humiliate him in this manner each time he returned drunk.

...He didn’t stop drinking but did not create a problem again. Although the group had to start collecting savings from scratch, the experience strengthened their commitment to work together.

“It’s like rice,” mused a MM leader, referring to how members gradually gain confidence in themselves, “when you put it on the fire, it doesn’t immediately get cooked. You have to wait a little while before the water starts boiling.”

A ‘Power-full’ Connection

WHEN the MM leader from a slum in Bhubaneswar went to her local corporator to ask for electricity connections, she was turned away. The politician wasn’t interested in entertaining this poor illiterate woman who did not seem in the least bit useful to him.

But she didn’t give up. Together with a group of women from her community, she went straight to the mayor. “You recently went to Mumbai and Pune to look at the housing and toilet projects there, right?” she asked, “and I heard you were really excited.” The mayor agreed. “Well, I belong to that same Federation and Mahila Milan in Mumbai and we need electricity connections here. Can you help us?” The mayor immediately called the corporator and asked him to fix up a meeting.

Surprised by the call from the mayor himself, the corporator invited the MM leader to his house the next evening. She was furious. After all, everyone knows no woman would go alone to a strange man’s house late in the evening! Instead, next morning, together with another 10 women from her slum, she showed up unannounced at the corporator’s door.

He was shocked, but greeted them respectfully and invited them to have breakfast. “I didn’t know you knew the mayor!,” he said. “Why did you need to go to him to ask for electricity? I was going to give it to you!” Of course, everyone was grateful to the Mahila Milan leaders when the slum got electricity...

The moral is : Communities, even if they are organised, initially need the help of large people’s movements to access resources due to the poor.



Citywatch



Alliance houses are registered jointly in women's and men's names, the woman's name coming first.

गठबंधन के घर महिला और पुरुष दोनों के नाम से रजिस्टर हाते हैं, पर महिला का नाम पहला होता है

NATIONAL SLUM DWELLERS FEDERATION

A. Jockin, President,
Byculla Area Resource Centre,
Meghraj Sesthi Marg, Municipal Dispensary,
Byculla, Mumbai: 400008
TEL: 022-23096730, FAX: 022-23887566,

SPARC

Khetwadi Municipal School Building, 2nd floor,
1st Khetwadi Lane, Near Alankar Cinema
Girgaum, Mumbai: 400004
TEL: 022-23865053/ 022-23858785
FAX: 022-23887566/ email: sparc@vsnl.in

MAHILA MILAN

Byculla Area Resource Centre,
Meghraj Sesthi Marg, Municipal Dispensary,
Byculla, Mumbai: 400008
TEL: 022-23096730, FAX: 022-23887566,

The Alliance works in the following cities in India:

MAHARASHTRA

Mumbai
Pune
Nashik

Ahmednagar
Pimpri
Nagpur
Thane
Panvel/Raigad
Sholapur
Kolhapur
Latur
Satara
KARNATAKA
Chickmagalur
Bangalore
Mandaya
Kolar Gold Fields
Bidar

Hubli
Dharwar
Mysore
TAMIL NADU
Chennai
Coimbatore
Tirupur
Madurai
Chengalpet
Theni
Tirunelveli
Valliyur
Thiruvalluvar
Vellore
Ambur
Vaniyambadi

Tirupattur
Kanchipuram
Tiruvannamalai
Pollur
Chengam
Arani
Trichy
Pallani
Tarapuram
Erode
Salem
Villupuram
Cuddalore
PONDICHERRY
Pondicherry
Karaikal

ANDHRA PRADESH
Hyderabad
Secunderabad
Chiralal
Guntoor
Vijaywada
Vizag
Warangal
UTTAR PRADESH
Kanpur
Lucknow
Benaras

GUJARAT
Vadodara
Ahmedabad
Surat
DELHI
Delhi
ORISSA
Bhubaneshwar
Cuttack
Puri
Konarak
Paradeep
WEST BENGAL
Kokkata
Kharagpur